भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1340
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : एमआईडीएच के लागत मानकों में संशोधन

1340. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू हुई थी और कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की उप-योजना के रूप में कार्यान्वित की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2013-14 से एमआईडीएच योजना के अंतर्गत सहायता के लागत मानकों और सहायता के पैटर्न में वृद्धि नहीं की गई है और इसको वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य 6.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ देश में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि 90 प्रतिशत से अधिक सुपारी का उपयोग केवल मीठी सुपारी और पान मसाला के लिए किया जाता है और इसके मूल्य संवर्धन और इसके सह-उत्पादों के विकास के संबंध में अनुसंधान की अधिक गुंजाइश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का दावणगेरे जिले में एक विशिष्ट अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जो भौगोलिक रूप से सुपारी की खेती और विपणन केन्द्रों के लिए उपयुक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रगति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम वर्ष 2005-06 में शुरू की गई थी, जो बाद में देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2014-15 से समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) नामक केंद्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत शामिल की गई है। कर्नाटक सहित सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एम.आई.डी.एच. के अंतर्गत शामिल हैं।

एम.आई.डी.एच. योजना के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप निम्नानुसार हैं:

- नर्सरी और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री
- क्षेत्र विस्तार और जीर्ण बागों का पुनरुद्धार
- संरक्षित खेती: नियंत्रित परिस्थितियों में उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की खेती
- जल संचयन संरचनाएं: वैयक्तिक और समुदाय के लिए फार्म पॉन्डस
- बागवानी मशीनीकरण, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) और एकीकृत नशीजीव प्रबंधन (आईपीएम)
- प्राइमरी प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज सहित फसल-उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर।
- किसानों का क्षमता वर्धन
- उत्कृष्टता केंद्र (सी°ओ°ई)

(ख) जी हां। वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक लागत मानदंड और सहायता पैटर्न को संशोधित नहीं किया गया है। तथापि, एमआईडीएच योजना के संशोधित लागत मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी हां। सुपारी की खेती लगभग 15 राज्यों में की जाती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9.638 लाख हेक्टेयर है और उपज 13.739 लाख टन है। सुपारी उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, जो देश के कुल उत्पादन का 70% से अधिक है। कर्नाटक में सुपारी के अंतर्गत 6.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जहां 10 लाख टन उत्पादन होता है।

(घ) सुपारी का उपयोग मुख्य रूप से चबाने के लिए किया जाता है। कई एल्कलॉइड की वजह से इसका उपयोग आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सा दवाओं में भी किया जाता है। सुपारी प्रोसेसिंग के अपशिष्ट से प्राप्त बाइ-प्रॉडक्ट टैनिनस के कई उपयोग हैं जैसे कपड़े रंगना, चमड़े की टैनिनग, फूड कलररिंग और मेटालिक साल्ट्स के साथ शेडस बनाने के लिए मोर्डेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपारी के नट्स में एक्स्ट्राक्टएबल फेट भी होती है, जो कन्फेक्शनरी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है।

(ङ) इस समय, कर्नाटक के दावणगेरे जिले में एक विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****